Severe Drought Situation in Palamu, Bihar

537. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some of the districts of Bihar especially Palamu are facing severe drought situation causing starvation deaths;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what measures Central Government have taken to ameliorate the conditions of the people; and

(d) whether Government have created an agency to monitor the relief work, if any?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) to (d): The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा कृषि नीति का विरोध

538. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर :**
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के किसानों ने सरकार की कृषि नीति के विरोध में, आलू की होली जलाई है, क्योंकि उन्हें अपने उत्पादों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या सरकार वर्तमान कृषि नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार कब तक नई कृषि नीति की घोषणा करना चाहती है/उसे कार्यान्वित करना चाहती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । बागबानी जिन्सों के मूल्यों में कमी आने की दशा में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त होने पर मण्डी हस्तक्षेप के बारे में कार्रवाई की जाती है ताकि किसानों को अफरा-तफरी में होने वाली बिक्री से बचाया जा सके । राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के साथ इन प्रचालनों में 50 प्रतिशत की हानि, यदि कोई हो, वहन करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करती है और मण्डी हस्तक्षेप मूल्य राज्य सरकार के परामर्श से निर्धारित किये जाते हैं । उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है, जिसमें आलू के मूल्यों में कमी आने और इस योजना को कार्यान्वित करने का उल्लेख किया गया हैं ।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने दीर्घावधि संदर्श में देश में कृषि विकास का ढांचा बनाने के लिए एक मसौदा कृषि नीति संकल्प तैयार किया है । इस मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए सदस्यों की टिप्पणियों से लाभ लेने के लिये मसौदा संकल्प की प्रतियां 23 दिसम्बर, 1992 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी गई है । अन्य बातों के साथ-साथ मसौदा संकल्प में यह दिया गया है कि सरकार, कृषक समुदाय को लाभकारी कृषि मूल्य देने को सुनिश्चित करने के लिए अपने उत्तरदायित्वों का वहन करेगी ।

Disaster management and reduction

539. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India comes in the disaster prone area being inflicted by floods, drought, cyclones and even earthquakes; and

(b) if so, what are the main programmes to be implemented by Government during the current Five Year Plan period for disaster management and reduction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) Yes, Sir.

(b) The programmes being implemented by Government during the current Five Year Plan for reducing the impact of natural disasters include:

(1) improvement of warning and forecasting systems.

(2) Drought Prone Area Programme,

(3) Desert Development Programme.

(4) Flood Management Schemes involving construction, raising and strengthening of embankments, improving drainage channels, antierosion and town protection works.

(5) Accelerated Rural Water Supply Programme.

(6) National Watershed Development Project for rainfed areas.

(7) Integrated Watershed Management in the catchments of flood prone rivers.

(8) Establishing Building Centres for technology transfer for construction of disaster resistant houses/buildings/relief shelters.

टालीगंज, पश्चिमी बंगाल में जट प्रौद्योगिकीय अनुसंधान प्रयोगशालायें

540. श्री मोहम्मद सलीम :
श्री सुकोमल सेन :
श्री राम नारायण गोस्वामी :
श्री सुनील बसुराय :
श्री मोहम्मद अमीन ।

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टालीगंज, पश्चिमी बंगाल में जूट प्रौद्योगिकीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं के कार्यकरण से संतुष्ट है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार इस एकक को फिर से चलाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है; और

(ग) क्या सरकार को सम्बद्ध क्षेत्र से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

Palm oil production in the country

541. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have drawn a massive plant to increase the palm-oil production in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the plan is being implemented and if so, the names of the states where it is being implemented;

(d) what is the year-wise production expected for the coming years; and

(e) the specific production plan during 8th Plan period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICUUL-TURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) Yes, Sir.

(b) An area of 7.96 lakh ha. has been identified in 11 States as suitable for oil palm cultivation. It is proposed to bring 80,000 ha. under oil palm cultivation during Eighth Plan.